

मोप्र० शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

डी-१८/१६  
क्रमांक / डी-१५/५६/२०१८/१४-३

वल्लभ भोपाल— भोपाल—४६२००४

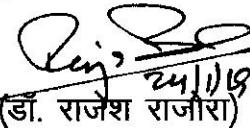
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2019

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सहकारिता विभाग,  
भोपाल ।

विषय:- जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आधार सीडेड ऋण खातों के आधारकार्ड के प्रमाणीकरण त्वरित एवं सूक्ष्म परीक्षणोपरान्त कराए जाने विषयक ।

जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत सहकारिता (बैंक अथवा PACS) से लिए गए फसल ऋण के आधार पर ऋण खाते को आधार सीडिंग के आधार पर हरी सूची में प्रदर्शित किया गया है। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) से लिए गए फसल ऋण खातों के संबंध में दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 के मध्य किसानों द्वारा ग्राम पंचायतों में जमा कराए गए हरे/सफेद/गुलाबी आवेदन पत्रों को पोर्टल पर इन्द्राज करने उपरान्त सहकारी बैंक शाखाओं में Secured login से डाटा सत्यापन के समय आधारकार्ड का प्रमाणीकरण किया जाना है। अनुरोध है कि सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) से लिए गए ऋण खातों के भले ही हरी सूची अथवा सफेद सूची में नाम होने की दोनों स्थितियों में ऐसे समस्त ऋण खातों के डाटा का सत्यापन एवं आधारकार्ड प्रमाणीकरण बैंक शाखाओं में मेप-आईटी अथवा MPSEDC या अन्य शासकीय संस्था की मदद से बैंक शाखाओं में सुचारू एवं पूर्ण परीक्षण उपरान्त ही पोर्टल पर किया जावे, इसकी त्वरित एवं पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे।

  
(डॉ. राजेश राजोरा)

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

डी-१८/१६  
पृ० क्रमांक / डी-१५/५६/२०१८/१४-३

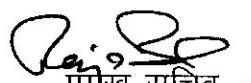
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि :-

01. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
02. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल ।

(2)

04. श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव वित्त सह आयुक्त, संस्थागत वित्त संचालनालय, भोपाल ।
  05. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
  06. आयुक्त सह पंजीयक, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, भोपाल ।
  07. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, भोपाल ।
  08. प्रबंध संचालक, अपेक्ष सैंक, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश सरकार

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग